पुराना है शुगर डी-कंट्रोल का मामला

बिजनेस भास्कर

देश में चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने की बहस बहुत पुरानी है और यह 70 के दशक से चली आ रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर गठित सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट को लेकर चर्चा गर्म है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि अगर चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया जाता है तो यह कई तरह से इस उद्योग के हित में होगा। भारत में चीनी का मुद्दा काफी संवेदनशील माना जाता है और इसका कारण है यह एक तरफ इससे जहां सारे देश के उपभोक्ताओं का हित जुड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस क्षेत्र से जनसंख्या का 7.5 फीसदी हिस्सा जुड़ा हुआ है।

चीनी क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक है जो देश में सबसे ज्यादा नियंत्रित हैं। इस क्षेत्र में गन्ने की कीमत और खरीद से लेकर चीनी तक के दामों का नियंत्रण सरकार के हाथ में है। इस क्षेत्र की एक बड़ी दिक्कत लेवी चीनी को लेकर है। चीनी मिलों को अपने कुल उत्पादन का दस फीसदी सरकार को बहुत कम कीमत पर देना होता है। इस चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश में वितरित किया जाता है। चीनी मिलों का कहना है कि इसके कारण उन्हें नुकसान होता है और यह बंद होना चाहिए।

देश में उत्पादित चीनी को प्लांटेशन व्हाइट शुगर कहा जाता है। यह कच्ची और रिफांइड शुगर के बीच का उत्पाद होती है। ज्यादातर मिलों के पास यूरोपियन स्टैंडर्ड की चीनी बनाने की तकनीक नहीं है। देश के चीनी उद्योग में चीनी को-ऑपरेटिव सेक्टर की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। इसकी भी कई समस्याएं हैं। सहकारी चीनी उद्योग को राज्य की संबंधित सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे फैसले लेने के लिए राज्य सरकारों के मेहरबानी पर निर्भर करना पड़ता है। ज्यादातर को-ऑपरेटिव चीनी मिलें आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं हैं। कुछ तो चालीस साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इससे उनका उत्पादन कम हो जाता है और वे फायदे में नहीं पहुंच पाती हैं। पिछले कुछ साल में सरकार पर कंट्रोल थोड़ा ढीला किया है। इसलिए उसने कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति भी दी है। शुगर इंडस्ट्री पूरी तरह बंटी हुई है और किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी तीन फीसदी से ज्यादा नहीं है।

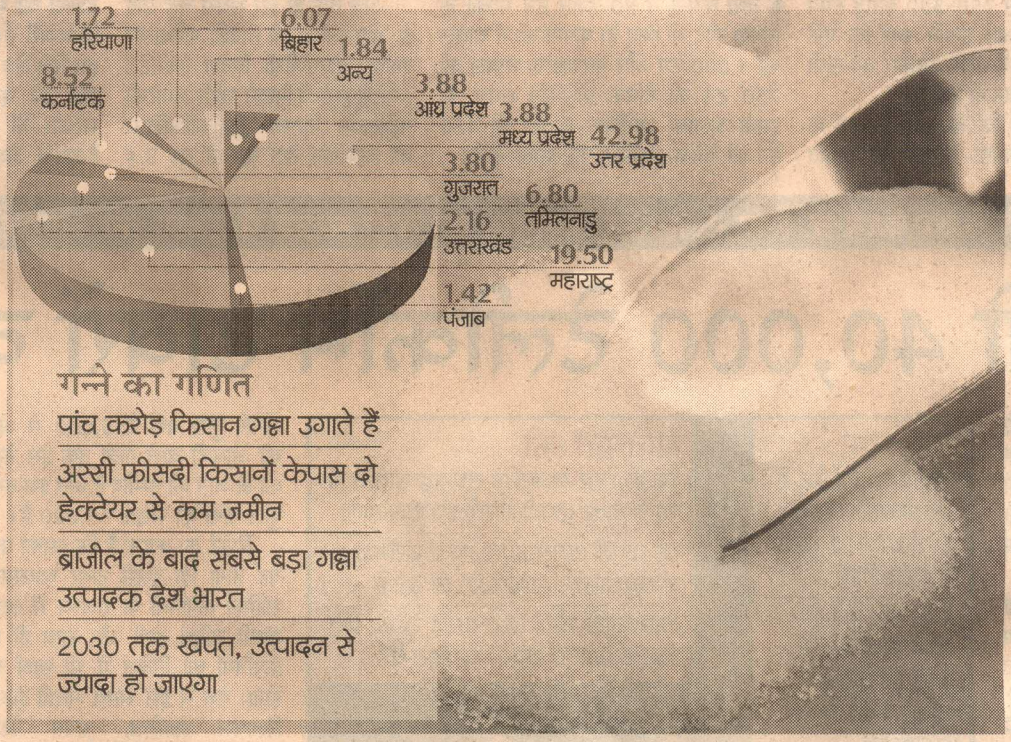

गन्ने का गणित

पांच करोड़ किसान गन्ना उगाते हैं

अस्सी फीसदी किसानों केपास दो हेक्टेयर से कम जमीन

ब्राजील के बाद सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भारत

2030 तक खपत, उत्पादन से ज्यादा हो जाएगा